**Increase in Installed Capacity of Newsprint Industry**

511. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to increase the installed capacity of newsprint industry in the country in the year 1982-83;

(b) if so, details of the said steps; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAIN DATT TIWARI): (a) Yes, Sir.

(b) Till recently, the National Newsprint and Paper Mills Ltd., Nepanagar, with an installed capacity of 67,500 tonnes per annum, was the only unit producing newsprint. The mill is undertaking a modernisation-cum-renovation programme to raise its installed capacity to a level of 75,000 tonnes. In addition, the newsprint project of Mysore Paper Mills, (capacity 75,000 tonnes per annum) and Kerala Newsprint Project of the Hindustan Paper Corporation Ltd. (Capacity 80,000 tonnes per annum) will also be in commercial production by 1982-83.

The undermentioned scheme have also been licensed for the manufacture of newsprint and are in preliminary stages of implementation:—

| | | |
|---|---|---|
| M/S | Tamil Nadu News Prints and Paper Ltd.. | 500,000 tonnes per annum |
| M/S | Century Pulp and Paper Ltd.. | 20,000 tonnes per annum |

Government would also encourage further proposals if any, received for manufacture of newsprint.

(c) Does not arise.

**खेतिहर तथा बागान श्रमिकों को कम मजूरी**

512. **श्री राम लाल राही** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतों, बागानों या कुछ अन्य स्थानों पर काम करने वाले निर्धन श्रमिकों को मालिक बहुत कम मजरी देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्धन श्रमिकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर सरकार कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर)**: (क) और (ख). कृषि और बागानों में नियोजनों तथा अधिकांश नियोजनों में, जहां श्रमिक अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं, मजदूरी की न्यूनतम दरें संबंधित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित की जाती हैं । इन मजदूरी-दरों को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है तथा उनके द्वारा उन्हें लागू किया जाता है । बागानों में, मजदूरी-दर द्विपक्षी य क रों द्वारा भी निश्चित की जाती हैं। अतः इन नियोजनों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में किसी नए कानून का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके ।

**छठी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन**

513. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो उनका स्वरूप और कारण क्या हैं ; और